प्रकाशनार्थ

पटना, 7 दिसंबर। बिहार के उप-मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बिहार ने पिछले चौदह वर्षों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सूचकों के लिहाज से काफी प्रगति की है। उन्होंने इस प्रगति के लिए नीतिगत और अकादमिक सुझाव देने में आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र (सीईपीपीएफ) की भूमिका और योगदान को रेखांकित किया। श्री मोदी 2008 में आद्री द्वारा स्थापित थिंक टैंक आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र (सीईपीपीएफ) की दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित **पब्लिक फाइनेंस : थ्योरी, प्रैक्टिस एंड चैलेंज** विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कर रहे थे। माननीय उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की आर्थिक विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक रही है जो राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। उन्होंने इसकी भी जानकारी दी कि बिहार राजस्व अधिशेष वाला राज्य रहा है और पिछले दशक में योजनागत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 से 2018 के बीच बिहार के बजट में सातगुनी वृद्धि हुई है। श्री मोदी ने बताया कि "राज्य ने पिछले 14 वर्षों के दौरान कभी भी ओवरड्राफ्ट नही लिया। बिहार में लोक ऋण प्रबंधन सीमा के अंदर रहा है। स्वास्थ्य, बिजली, कृषि आदि क्षेत्रों में गत दशक के दौरान उल्लेखनीय सुधार हुआ है।" उन्होंने बिहार के विकास में अभी तक निभाई गई भूमिका के लिए आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र (सीईपीपीएफ) की भूमिका को दिल से स्वीकार किया।

आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र दशम वर्षगांठ व्याख्यान देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डा. वाइ.वी. रेड्डी ने कहा कि "भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्र रूप से काम करता है लेकिन राज्य के साथ सघन समन्वय बनाए रखता है"। उन्होंने बताया कि वित्तीय अस्थिरता और राजनीतिक अस्थिरता साथ-साथ चलते हैं। उन्होंने लेखाकरण के सिद्धांतों के महत्व को भी रेखांकित किया।

प्रख्यात लोक वित्त विशेषज्ञ श्री एम. गोविंद राव ने 150 से भी अधिक श्रोताओं का ध्यान लोक वित्त के लिए नीति निर्माण में शोध और पक्षपोषण के योगदान पर आकर्षित किया। उन्होंने व्यापक बजट आबंटन में क्षेत्रों के लिए आबंटन के महत्व को रेखांकित किया और बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक को सरकार के साथ सहमति और सघन समन्वय बनाए रखकर काम करना चाहिए।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम), अहमदाबाद के निदेशक श्री एरॉल डि'सूजा ने कहा कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति का समन्वय वृहद आर्थिक प्रबंधन की अनिवार्य आवश्यकता है। उन्होंने यह भी टिप्पणी की कि किसी देश के लोक ऋण के उसकी राजकोषीय सीमा तक पहुंच जाने के बाद इस बात की गुंजाहश होती है कि वह उसकी ऋणवृद्धि का मान घटा देगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति राज्य की दो भुजाएं हैं और उनमें समन्वय जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य को वित्तीय निवल संपत्ति के नकारात्मक होने की चिंता नहीं करनी चाहिए।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम), अहमदाबाद के श्री सुखपाल सिंह ने भारत में कृषि उत्पाद बाजार में सुधार संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने रेखांकित किया कि देश कृषि संकट का सामना कर रहा है और कहा कि कृषि उत्पादों के बेहतर विपणन के जरिए इस संकट को दूर करने में राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।

आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र (सीईपीपीएफ) के निदेशक डॉ. शैबाल गुप्ता ने स्वागत भाषण करते हुए पिछले दस वर्षों के दौरान आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र (सीईपीपीएफ) के क्रमिक विकास का संक्षेप में उल्लेख किया। उन्होंने टिप्पणी की कि आज की वैश्वीकृत दुनिया में लोक वित्त के सामने बहुमुखी चुनौतियां हैं। बिहार जैसे राज्य में ये चुनौतियां और भी जटिल और गहरे असर करने वाली हो जाती हैं जहां लोक वित्त के मुद्दे विकास संबंधी तात्कालिक आकांक्षाओं से सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने विकास संबंधी योजना निर्माण में राज्य की शीर्ष भूमिका पर बल दिया और पिछले दस वर्षों में राज्य सरकार को नीतिगत विकास और सहायता उपलब्ध कराने में नीति विषयक थिंक टैंक के बतौर आर्थिक नीति एवं लोक वित्त केंद्र (सीईपीपीएफ) के योगदान का उल्लेख किया।

आद्री के अध्यक्ष और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इमेरिटस प्रोफेसर श्री अंजन मुखर्जी ने इस अवसर पर धन्यवाद ज्ञापन किया।

(अंजनी कुमार वर्मा)